

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.(78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017 659

दिनांक 25.05.2018

संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषय—ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत।

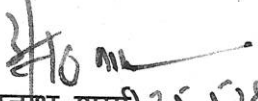
प्रसंग—विभागीय पत्र क्र0एफ.(78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1974
दिनांक 10.05.2017

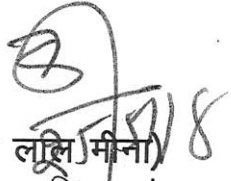
उपरोक्त प्रासांगिक पत्र द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प. 9(6) राज-6/2000/10 दिनांक 07.09.2017, 30.11.2017 एवं 10.05.2018 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/ प्रतिबंधित श्रेणी /सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड़ कर यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड़ कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.01.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे करवाया जाकर, तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किये जाने उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी भूमि के रहवासियों को पट्टे जारी किये जाने है।

राज्य में राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार --2018, दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा अभियान से पूर्व एवं अभियान के दौरान ऐसी भूमि के रहवासियों को दिए गए पट्टे की प्रगति की सूचना ई-पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाई जावे। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में अभियान के दौरान उक्त सर्वे एवं पट्टे जारी करने का कार्य नहीं हुआ है उन पंचायतों में भी सर्वे एवं पट्टे जारी करने का कार्य कराया जावे और जिन ग्राम पंचायतों में अभियान होना है उनमें अभियान से पूर्व नियत प्रक्रिया को अपनाकर अभियान दिवस पर पट्टे जारी कराने का कार्य सुनिश्चित करें।

आप इस अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की संयुक्त बैठक लेकर उनको निर्देशित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 1974 दिनांक 10.05.2017 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक ऐसे भूमि के रहवासियों को पट्टे जारी हो सकें।

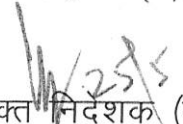
आपके जिलें में आयोजित न्याय आपके द्वार -2018 के अभियान की प्रगति संलग्न प्रारूप में प्रतिदिन ई-पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व में आयोजित अभियानों की प्रगति की सूचना भी उक्त पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराई जावे।


(अजिताभ शर्मा) 25.5.18
शासन सचिव
राजस्व विभाग


(कुंजी लाल मिश्रा)
शासन सचिव एवं
आयुक्त, पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री राजस्व विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त) को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।
9. एसीओ, पंचायती राज विकास एवं विभागीय अधिकारी पर डपलो -
कवाड जिले के/उ/य/अ/ई।


संयुक्त निर्देशक (मो0)
पंचायती राज विभाग

पंचायत शाह - सरकारी भूमि पर पट्टी पर ~~विवाद~~ 31/05/20

REGISTRATION



नोट: कृपया ध्यान दें कि यह सेवा केवल सरकारी भूमि के लिए ही उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि यह सेवा केवल सरकारी भूमि के लिए ही उपलब्ध है।

नोट: कृपया ध्यान दें कि यह सेवा केवल सरकारी भूमि के लिए ही उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि यह सेवा केवल सरकारी भूमि के लिए ही उपलब्ध है।

निर्वाह अधिकारी

निर्वाह अधिकारी

पंचायत समिति

निर्वाह

पंचायत समिति

पंचायत समिति

सरकारी भूमि पर पट्टी पर आवास गृहों के पट्टी से सम्बन्धित सूचना

सर्वे में विहित हुआ परिवार

उपरोक्त अधिकारी द्वारा पट्टी पर आवास गृहों के पट्टी पर परिवार कि सूचना

वर्कसीयर द्वारा राजस्व रिकार्ड में सरकारी भूमि में दफ्त किए गए परिवार की सूचना

ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टी की सूचना

नियम 157 के तहत सूचना भवनों का विवरण

नियम 157 के तहत वर्ष 2003 तक के कच्ची एवं निष्पूरक विवरण

नियम 158 के तहत भूमि आवंटन विधायी दर पर पट्टी आवंटन विवरण

नियम 158 के तहत भी.पी.एस. एवं सशिक्षित युवा के परिवारों को निष्पूरक भू-आवंटन विवरण

नियम 157 के तहत भवनों का विवरण

नियम 157 के तहत भवनों का विवरण

SEARCH